



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1936 (श०)
(सं० पटना ९८०) पटना, बुधवार, ३ दिसम्बर २०१४

सं० ३ए-४-प्रो०-०३/२०१४-१०९३६ (वि०)
वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक २७ नवम्बर २०१४

विषय:- सरकारी सेवक को ए०सी०पी० नियमावली-२००३ की कंडिका-४(५)(ii) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही आदि या प्रोजेक्ट के योग्य नहीं पाये जाने के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ १२ वर्ष के बाद न देकर बिलंब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर होने वाले प्रभाव के संबंध में ।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि ए०सी०पी० नियमावली, २००३ की कंडिका-४(५)(ii) में निम्नांकित प्रावधान किया गया है—

“यदि सरकारी सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही आदि के चलते या प्रोजेक्ट के योग्य नहीं पाए जाने के चलते ए०सी०पी० योजना के अधीन प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ ठीक १२ वर्ष के बाद न

देकर विलंब से दिया जाता है तो ए०सी०पी० योजना के अधीन दूसरा वित्तीय उन्नयन प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि से १२ वर्षों के बाद दिया जाएगा।”

(2) विभागीय अधिसूचना सं०-७५४९, दिनांक १३/०७/२०१० के द्वारा ए०सी०पी० नियमावली, २००३ को निरसित किया गया है तथा विभागीय संकल्प संख्या-७५६६, दिनांक १४/०७/२०१० के द्वारा राज्य कर्मी को वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए पूर्व की ए०सी०पी० योजना नियमावली, २००३ को अधिक्रमित करते हुए रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, २०१० (एम०ए०सी०पी०एस० योजना नियमावली-२०१०) लागू कर दिया गया है जो दिनांक ०१ जनवरी, २००९ के प्रभाव से प्रवृत्त है। रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, २०१० के तहत राज्य सेवकों को एक ही ग्रेड वेतन में लगातार १०, २० और ३० वर्षों की सेवा पूरी करने पर ठीक उपर के ग्रेड में तीन वित्तीय उन्नयन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(3) वित्त विभाग से कतिपय प्रशासी विभागों द्वारा ऐसे मामले पृष्ठांकित किए जाते रहते हैं जिनमें यह परामर्श माँगा जाता है कि प्रथम वित्तीय उन्नयन में विलंब होने की स्थिति में बाद के वित्तीय उन्नयनों की तिथि किस प्रकार प्रभावित होगी।

(4) एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य सरकार के किसी कर्मी को ए०सी०पी० नियमावली, २००३ की कंडिका-४(५)(ii) के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन विलंब से प्राप्त होता है तथा द्वितीय उन्नयन उक्त नियमावली के निरसित होने के पूर्व अनुमान्य नहीं होता है तो ऐसे कर्मी को एक ही वेतनमान में १० वर्ष की सेवा पूरी होने पर रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, २०१० के तहत द्वितीय वृत्ति उन्नयन दिनांक ०१/०१/२००९ या १० वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि, जो बाद में हो, से अनुमान्य होगा। उदाहरणस्वरूप किसी कर्मी की नियुक्ति की तिथि ०२/०२/१९७९ तथा सेवानिवृत्ति की तिथि ३१/०८/२०१५ है उक्त कर्मी को ए०सी०पी० नियमावली, २००३ की कंडिका ४(५)(ii) के तहत किसी कारण दंडादेश या विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता में विलंब आदि के चलते प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ दिनांक ०९/०८/१९९९ की बजाय विलंब से दिनांक ०९/०८/२००४ के प्रभाव से प्राप्त होता है तो द्वितीय वित्तीय उन्नयन रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, २०१० के तहत दिनांक ०९/०८/२०१४ के प्रभाव से अनुमान्य होगा।

विश्वासभाजन,

प्रभात शंकर,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) ९८०-५७१+१०-८००१०८०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>